TELCOS TO BAN CHINESE GEAR

There is an undercurrent of anti-China sweeping across India and government has asked telecom companies to not depend on Chinese companies. Meanwhile COAI Cellular Operators' Association of India has strongly recommended that geopolitical issues are the under the purview of the government and should be kept separate from corporate decisions.

The Association has members like Bharti Airtel and Vodafone Idea -- further said that so far, the government had not mandated exclusion of any vendors' equipment from private operator networks. The government has decided to ask state-owned Bharat Sanchar Nigam Ltd (BSNL) not to use Chinese telecom gear in its 4G upgradation, which is being supported as part of the company revival package, according to sources. Confederation of All India Traders has also called for a boycott of Chinese products in protest to border standoff.

BSNL & MTNL will not use Chinese equipment in upgradation to 4G networks, which is being supported by its revival package.

Chinese handset maker Oppo cancelled the livestream launch of its flagship 5G smartphone.

Oppo, which ranks among the top five smartphone vendors in India, four of the five top smartphone brands in India (Xiaomi, Vivo, Realme and Oppo) are from China and accounted for almost 76 per cent share of smartphones shipped in India in the quarter ended March 2020.

South Korea's Samsung, which ranked third and cornered 15.6 per cent share of shipment in the said quarter is the only non-Chinese firm in the top five tally.

Huawei has invested more than US$ 2 billion in India in the last 20 years. Huawei and ZTE together have a share of a fourth of India's telecom equipment market. Meanwhile Vodafone Idea and Bharti Airtel could see a minimum 20-30% jump in network gear procurement costs if they have to procure gear from non Chinese companies. ■

चीनी उपकरण को प्रतिबंधित करेंगे टेल्को

पूरे भारत में चीन विरोधी भावना अपने चरम पर है और सरकार ने अब दूरसंचार कंपनियों से कहा है कि वे चीनी कंपनियों पर निर्भर नहीं रहें। इस बीच सीओएआई सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दृढ़ता से सिफारिश की है कि भू-राजनीतिक मुद्दे सरकार के दायरे में है और इन्हें कॉरपोरेट फैसलों से अलग रखा जाना चाहिए।

एसोसिएशन में भारती एयरटेल व वोडाफोन आइडिया जैसे सदस्य हैं–ने आगे बताया है कि अभी तक, सरकार ने निजी ऑपरेटर्स नेटवर्क से किसी भी विक्रेताओं के उपकरण को बाहर करने का आदेश नहीं दिया है। सरकार ने राज्य की स्वामित्व वाली भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को अपने 4जी अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करने का फैसला लेने को कहा गया है, जिसे कि सूत्रों के अनुसार कंपनी के पुर्नजीवित करने के पैकेज के हिस्से के रूप में इसका समर्थन किया जा रहा है। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स ने सीमा गतिरोध के विरोध में चीनी उत्पादों के बहिष्कार का भी आहवान किया है।

बीएसएनएल व एमटीएनएल 4जी नेटवर्क के लिए अपग्रेडशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिसे कि इसके पुनरूद्धार पैकेज द्वारा समर्थित किया जा रहा है। चीनी हैंडसेट निर्माता ओप्पो ने अपने प्रमुख 5जी स्मार्टफोन के लाइवस्ट्रीम लॉन्च को रद्द कर दिया।

ओप्पो, जो कि भारत में पांच शीर्ष स्मार्टफोन विक्रेताओं में शुमार है, भारत में पांच सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांडों में चार (शियोमी, वीवो, रियलमी व ओप्पो) चीन की हैं और मार्च 2020 को समाप्त तिमाही में भारत में भेजे गये लगभग 76 प्रतिशत स्मार्टफोन की हिस्सेदारी है।

दक्षिण कोरिया का सैमसंग, जो कि तीसरे स्थान पर है और उक्त तिमाही में शिपमेंट के 15.6 प्रतिशत हिस्सेदारी के साथ पांच प्रमुख में एकमात्र गैर-चीनी कंपनी थी।

हुआवेई ने पिछले 20 वर्षों में भारत में 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का निवेश किया है। हुआवेई व जीटीएल के पास भारत के दूरसंचार उपकरण बाजार का एक चौथाई हिस्सा है। इस बीच वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल नेटवर्क को उपकरण खरीदी लागत में न्यूनतम 20-30% की उछाल देखने को मिल सकती है यदि उन्हें गैर चीनी कंपनियों से उपकरण खरीदने पड़े। ■